

भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार मेट्रो विस्तार की योजना बनाये- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो की प्रगति बैठक में सभी प्रमुख मार्गों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के निर्देश दिये



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति को लेकर अधिकारियों की बैठक की।

(मानसरोवर-अजमेर रोड चौराहा) की परियोजनाओं को गति देने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री शर्मा ने जनसंख्या घनत्व एवं दैर्घिक के दबाव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में दिल्ली रोड एवं

सीकर रोड सहित, अन्य मार्गों की दिशा में मेट्रो विस्तार की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि जयपुर के प्रमुख मार्गों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाए।

बैठक में बजट वर्ष 2025-26 की अनुपालना एवं मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, आमेर, जगतपुरा, बगराना (आगरा रोड) एवं हीरापुरा तक मेट्रो विस्तार के मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने जेडीए एवं जयपुर मेट्रो को बेहतर

युद्ध में अपनी बिचौलिए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करेगा। सीजफायर पाकिस्तान द्वारा "मध्यस्थता" के तहत हुआ है और पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए परामर्श की पेशकश की। हालांकि, कमजोर सीजफायर अब और भी कमजोर दिखने लगा है।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने का, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग अभी भी अव्यवस्थित है। ईरान ने चेतावनी दी है कि केवल वे जहाज, जिनकी मंजूरी ईरानी अधिकारियों ने दी है, सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर सकते हैं। यूके ने यहां मुक्त पारगमन की मांग की है, जबकि ईरान पहले ही इसके लिए कुछ शुल्क की बात कर रहा है। सीजफायर को बनाए रखने में एक और बड़ी बाधा यह है कि क्या यह लेबनान और हिज्बुल्लाह के ऑपरेशनों को कवर करता है या ये वर्तमान सीजफायर के दायरे से बाहर हैं।

पाकिस्तान ने पहले ही अपने दायरे से बाहर जाकर यह कहा कि लेबनान

ये तो स्थायी शांति होने के आसार नहीं हैं।

सीजफायर समझौते का हिस्सा है, जबकि ट्रंप ने इजरायल के लेबनान ऑपरेशन को सीजफायर समझौते के बाहर रखा। एक और बड़ी समस्या यह है कि क्या ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को जारी रख सकता है। अमेरिका और इजरायल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान का अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम छोड़ना इस पूरी प्रक्रिया का मूल है।

ईरान इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान द्वारा परमाणु कार्यक्रम को छोड़े बिना और संवर्धित यूरेनियम को सौंप बिना किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सकता।

अमेरिका का दावा है कि ईरान के पास लगभग 800 पाउंड संवर्धित

यूरेनियम है, जो हथियार बनाने योग्य है। ईरान का कहना है कि उसका संवर्धन कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए है। हालांकि, ऊर्जा संयंत्रों को केवल 3.45 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम चाहिए, जबकि ईरान का स्टॉक 6.5 प्रतिशत या उससे अधिक संवर्धित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जोर देकर कहते हैं कि ईरान के वर्तमान 10-बिंदु मांग चार्टर पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। ईरान कहता है कि 10-बिंदु कार्यक्रम को स्वीकार किए बिना कोई बातचीत नहीं हो सकती। इस प्रकार, दोनों पक्ष उम्मीद कर रहे हैं कि यह कमजोर शांति मजबूत शांति में बदल जाए और जंग बंद हो। लेकिन इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में इतना भारी बमबारी की कि मृतकों की संख्या आधाघण्टा तक बढ़ गई। ईरान ने भी अमेरिकी क्षेत्रीय पड़ोसियों पर कुछ मिसाइलें और ड्रोन दागे, सीजफायर समझौते की परवाह किए बिना।

'ट्रंप ने दबाव डाला था ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसने पूरे संघर्ष के दौरान अपनी तटस्थता पर जोर दिया था।

मंगलवार को ट्रंप की समयसीमा नजदीक आने पर, पाकिस्तान के फोल्ड मार्शल ने ट्रंप, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और विशेष दूत स्टीव वित्कोफ सहित, शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों को कई कॉल किये। इसके बाद उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से दो सप्ताह के प्रस्ताव के बारे में बात की, जिसे जल्दी ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया। लेकिन परदे के पीछे, "न्यूयॉर्क टाइम्स" की रिपोर्ट के अनुसार, वाइट हाउस ने इस बयान को पहले ही देख लिया था और शहबाज शरीफ द्वारा इसे पोस्ट करने से पहले मंजूरी दे दी थी।

लेकिन शरीफ, जिन्होंने इस सौदे को पाकिस्तान की पहल के रूप में पेश किया, अपने पोस्ट के शीर्ष पर लिया विषय (सबजैक्ट) "ड्राफ्ट - पाकिस्तान के पीएम का संदेश एक्स" हटाना भूल गए। कुछ समय बाद, जब ट्रंप ने होर्मुज जलसंधि खोलने के लिए अपना पहला अल्टीमेटम दे दिया, इस बीच मुनीर और अन्य वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी, ईरानी राजनीतिक और सैन्य नेताओं और वाइट हाउस के बीच संदेश

पहुंचाने में व्यस्त थे। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने इस्लामाबाद को शांति शिखर सम्मेलन के स्थल के रूप में प्रस्तुत किया, अमेरिका द्वारा ड्राफ्ट किए गए प्रस्ताव के 15-बिंदु साझा किए और 45 दिन से लेकर दो सप्ताह तक के युद्धविराम के विकल्प पेश किए। ईरान ने इसके जवाब में अपने पांच और दस-बिंदु वाला प्रस्ताव भेजा।

दोनों पक्षों की मांगों में काफी दूरी थी लेकिन समय के साथ ईरान कथित रूप से, अपने यूरेनियम के भंडार पर सीमाएं स्वीकार करने और उन्हें कम करने के विचार के प्रति सहमत हो गया। वार्ता से परिचित लोगों के अनुसार, अराघची और तेहरान के अन्य राजनीतिक नेताओं ने कई दिन पहले ही अस्थायी होर्मुज युद्धविराम पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। लेकिन उन्हें इस्लामिक रिवालयूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आई आर जी सी), जो ईरान की प्रमुख सैन्य और राजनीतिक शक्ति है, से अंतिम मंजूरी लेने में कठिनाई हो रही थी। सप्ताहों की भारी अमेरिकी और इजरायली बमबारी के बाद, युद्धविराम को लेकर आई आर जी सी विभाजित था। सूत्रों ने कहा कि ईरानी बलों के कुछ तत्व युद्ध समाप्त करने, होर्मुज पर नियंत्रण ढीला करने और अमेरिकियों के साथ वार्ता फिर से शुरू करने के

विरोध में थे। इसके बाद मंगलवार को एक ईरानी ड्रोन हमले ने सऊदी पेट्रोकेमिकल केन्द्र जुबैल को निशाना बनाया, जिससे एक पाकिस्तानी अधिकारी ने "वार्ता को विफल करने का आखिरी प्रयास बताया।" इस्लामाबाद, जिसका सऊदी अरब के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता है, ने इस पर आक्रोशपूर्व प्रतिक्रिया दी, और तेहरान को संकेत दिया कि ये हमले शांति प्रयासों को नष्ट कर सकते हैं और ईरान को अलग-थलग कर सकते हैं।

अब तक, पाकिस्तान, जिस पर ईरान ने हमला नहीं किया है, ने संघर्ष के दौरान तटस्थ रहने की कोशिश की, जबकि सऊदी अरब पर कई बार मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। इसके बाद, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बुधवार दोपहर को शरीफ के साथ हुए फोन-कॉल में, वार्ता के लिए प्रतिनिधि इस्लामाबाद भेजने पर सहमत हो गए।

बारामती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फडणवीस के एक फोन के बाद ही यह फैसला लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बारामती उपचुनाव से कांग्रेस का उम्मीदवार वापस लेने की घोषणा कर दी।

शुक्रवार को नीतीश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संभावना है। शाम को भाजपा ने बिहार से सम्बन्धित एक विशेष बैठक निर्धारित की है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य मंत्री नित्यानंद राय को शीर्ष उम्मीदवार माना जा रहा है।

11 फरवरी को नीतीश पटना लौटेंगे और आगे दो दिनों तक वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसका कारण यह है कि हिन्दू 'खरमास' 13 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। भाजपा नेता चाहते हैं कि नये मुख्यमंत्री 14 अप्रैल को शपथ लें। संभावना है कि कुमार 13 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। यह एक विडंबना ही है कि कुमार को खरमास

अवधि के दौरान ही राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेनी पड़ रही है।

कुमार, जो कद्दावर समाजवादी नेताओं में अंतिम नेता हैं, ने अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण का अन्त अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से किया है। उन्होंने भी अपने पूर्ववर्तियों का उदाहरण अपनाया और सत्ता को भाजपा के साथ चलाया और अन्त में उसी को सौंप दिया।

जॉर्ज फर्नांडीस ने अपनी समता पार्टी का भाजपा के साथ तालमेल रखा और वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री बने। राम विलास पासवान, शरद यादव और खुद कुमार भी भाजपा सरकार में केन्द्रीय मंत्री रहे। हाल ही में, उपेन्द्र कुशवाहा जैसे लोग भी भाजपा के साथ तालमेल बैठा चुके हैं।

कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करिब आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किये जाने का मुद्दा भी उठाया है, क्योंकि इस प्रकार से भाजपा चुनाव में महिला मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, भले ही विधेयक पास न हो।

लेकिन भाजपा अपने नाटकीय प्रदर्शन और ड्रामेबाजी के लिए जानी जाती है और विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, ममता बनर्जी और तमिलनाडु में स्टालिन पर हमले का कोई अवसर नहीं चूकती। भाजपा के लिए सब कुछ चुनाव केन्द्रित है और यह देखना होगा कि वे चुनाव जीतने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं।

क्या राघव चड्ढा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ ही, राजनीतिक हलकों में वैकल्पिक परिदृश्यों पर चर्चा हो रही है, जैसे जिनमें पार्टी में पुनः मेलजोल से लेकर अन्य राजनीतिक मंच पर जाने जैसी चर्चाएं शामिल हैं। फिलहाल, ये सभी केवल अटकलें हैं।

स्पष्ट यह है कि चड्ढा की राजनीतिक यात्रा एक मोड़ पर है। उनके हाल के संकेत-सूक्ष्म लेकिन जानबूझकर दिए गए हैं, ने यह सुनिश्चित किया है कि वे चर्चाओं का हिस्सा बने रहें, भले ही पार्टी में उनका औपचारिक पद कमजोर दिख रहा हो। यह पल एक बड़े राजनीतिक कदम में बदलता है या आप के भीतर पुनर्संयोजन तक सीमित रहता है, यह आने वाले महीनों में पार्टी के भीतरी समीकरणों पर निर्भर करेगा। तब तक,

चड्ढा का दिलचस्प विचार राजनीतिक पर्यवेक्षकों की जिज्ञासा बनाए रखेगा।

'होर्मुज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश में एलपीजी संकट से लड़ने की कोशिशें कर रही है। फिलहाल तो देश में एलपीजी गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी हुई है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में हर दिन 58 लाख से ज्यादा घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं कमशियल एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता को भी बढ़ा दिया गया है, जो अब करीब 70 फीसदी तक पहुंच गई है।

कल्याण
ज्वेलर्स

Auspicious Beginnings

UP TO **50% OFF**
ON MAKING CHARGES

KALYAN SPECIAL 1g GOLD RATE ₹14100 | SAVE ₹500 per gm | MARKET 1g GOLD RATE ₹14600

OPEN ON ALL DAYS

JAIPUR: FLAGSHIP STORE: TONK ROAD - PH: 96025 33433 | VAISHALI NAGAR - PH: 91158 03333 | UDAIPUR - PH: 88756 78133
JODHPUR - PH: 94133 12103 | KOTA - PH: 91459 50033 | BIKANER - PH: 80033 93933 | SRI GANGANAGAR - PH: 74249 65433
AJMER - PH: 77424 13156 | HANUMANGARH - PH: 87690 57533 | MANSAROVAR - PH: 93562 25333

FOR MORE DETAILS CONTACT US ON TOLL FREE NUMBER: 1800 425 7333 | WWW.KALYANJEWELLERS.NET | FOLLOW US ON @FB

BUY ONLINE @ WWW.CANDERE.COM | FOR FRANCHISE ENQUIRIES WRITE TO FRANCHISEE.ENQUIRY@KALYANJEWELLERS.NET

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

पोषण पखवाड़ा
9 अप्रैल से 23 अप्रैल, 2026

राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के कीर्तिमान

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान में अग्रणी राजस्थान

उपलब्धियां

- राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में प्रथम स्थान
- राष्ट्रीय पोषण माह में द्वितीय स्थान
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान

कुपोषण पर सार्थक प्रहार

- पूरक पोषाहार कार्यक्रम (6माह से 6वर्ष के बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं हेतु)
- मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना (गर्भवती महिलाओं के लिए)
- मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना (3 से 6 आयुवर्ग के बच्चों के लिए)
- दुग्धयुक्त बालाहार (अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए)
- पोषण अभियान तथा जिम्मेदार पुरुष अभियान (जन जागरूकता के लिए)
- AMMA कार्यक्रम (समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन हेतु)

आईसीडीएस ने है ठाना - सुपोषित, शिक्षित, विकसित राजस्थान

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी